



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपबंध (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 470] वह दिल्ली, मण्डलवार, अक्टूबर 31, 1972/कालिक 9, 1894

No. 470] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 31, 1972/KARTIKA 9, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation

## MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 31st October 1972

**S.O. 685(E)/18A/IDRA/72.**—Whereas the Central Government is of the opinion that Indore Malwa United Mills Limited, Indore, an industrial undertaking in respect of which an investigation has been made under section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) is being managed in a manner highly detrimental to public interest.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 18A of the said Act, the Central Government hereby authorises the M.P. State Textile Corporation (hereinafter referred to as Authorised Controller to take over the management of the whole of the said undertaking, namely Indore Malwa United Mills Limited, Indore, subject to the following terms and condition, namely:

- (i) The Authorised Controller shall comply with all directions issued from time to time by the Central Government.
  - (ii) The Authorised Controller shall hold office for five years from the date of publication in the official gazette of this notified order.
  - (iii) The Central Government may terminate the appointment of the Authorised Controller earlier, if it considers it necessary to do so.
2. This order shall have effect for a period of five years commencing from the date of its publication in the official gazette.

[No. F. 3/21/72-CUC.]

K. S. BHATNAGAR, Jt. Secy.

श्रीद्वौगिक विकास मंत्रालय

(श्रीद्वौगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 31 अप्रैल 1972.

का० आ० 685(अ)/18ए/आई० डी० आर० ए०/72—यतः केन्द्रीय सरकार की यह गथ है कि इन्दौर मालवा यूनाइटेड मिल्स लि०, इन्दौर का, जो एक एंसा श्रीद्वौगिक उपकरण है जिसके सम्बन्ध में उच्चोग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की द्वारा 15 के अधीन जांच की गई है, प्रबन्ध इस दृंग से किया जा रहा है जो सार्वजनिक हित के लिए बहुत अहितकर है।

यतः अब उक्त अधिनियम की धारा 18-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एन्टद्राग्रा मध्य प्रदेश गजय वस्त्र नियम की (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकृत नियंत्रक कहा गया है) उक्त मम्पूर्ण उपकरण अर्थात् इन्दौर मालवा यूनाइटेड मिल्स लि० इन्दौर का प्रबन्ध नियमित्रित निबन्धनों और गतों के अद्यधीन प्रहृण करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात् :—

- (1) प्राधिकृत नियन्त्रक, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये सभी नियन्त्रणों का अनुपालन करेगा।
- (2) प्राधिकृत नियन्त्रक इस अधिसूचित, आदेश के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष के लिए कार्यभार सम्भालेगा।
- (3) यदि केन्द्रीय सरकार आवश्यक समझे तो वह प्राधिकृत नियन्त्रक की नियुक्ति को इससे पूर्व रद्द कर सकती है।

यह आदेश शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रारम्भ होने वाली पांच वर्ष की कालाबधि के लिए प्रभावी रहेगा।

[मं० फा० 3/21/72-सी० य० सी०]  
के० एस० भटनागर, संयुक्त सचिव।